

आज पढ़िए अंतिम कड़ी
एक तरफ सब्सिडी और गरीबों के कल्याण के सरकारी खर्च पर बेतहाशा वृद्धि हुई पर उसका परिणाम नीचे तक नहीं पहुंच रहा था. कुछ राज्यों में तो जितने घर थ. कहीं उससे आधिक राशन कार्ड थे. इस तरह भारत का भविष्य और विकास, भ्षष्टाचार के अंधेरें ने निगल लिया था . 'आधार' ने उम्मीद पैदा की है कि सही आदमी को पहचानकर उसकी मदद की जाये . सीधे उसके हाथ में उसका हिस्सा देकर, पहुंचाकर, ताकि वह अपनी नियति का खुद मालिक बन सके. किसी बिचोलिये या भ्रष्ट अफसर के रहमोकरम या दया पर मयस्सर न रहे.







 रह रहे हैं, जांा हमरे भविषा समाज, कासकाज प्रसनता पींवार और फसा को लेक्र अनगिनत सवाल हैं, पर किर्स के पस इनका उत्र नहीं हैं. इस पुस्तक में लंद्त में मई 2002 में हुए एक प्रदोग का उल्लेख है.

आधार के प्रसंग में वह जाने--सीखने योय्य है. लंक्ष (युर्रेप का वितीय केंद्र) के मशार स्वधायए माइल जौगहे पर, पिछले चालीस वर्षो से तेरह
आवामाचदोन (ोमलय लोग चालीस वर्षं ंे ये तेरह, त्रिटेन की पलिस अदालत और एनजीओं के लिए मुसीका बने हो थे. इन तेरह लोगों पर श्रिटेन सरकर के तीनों विभागों (पलिस, अवलत और सामाजक सेवा देनेवाली संस्थाए) का कुल मिलाकर वर्षिक खर्च चार लाख पोंड या 6.50 लाख डौतर बा. वह भारी मुसीवत थी. लंदन स्थित एक संस्था त्राडवे ने एक मोलक निणंय किया कि झत तेरह अवासवितीन सडक रोज खाने-राले का बंदोगय साखार तारा होगा गानन सीधे उनके होथं में पैसा. हेंक् पर 3000 पंड सालाना खर्चं करने के लिए सरकार व्यवस्था करोगी. वे सीषे करें या अपने सलाह कार के मध्यम से खर्च करें, वह उनके विवेक पर. चालस वर्षो से सडक पर रहनेवले उन लोगों की जरूतेंते क्या थीं. एक टेलिफोन. एक शब्दकोश, सुने में मदद कस सेवाता एक सहायक बत्र इस तरह हरे की प्रालगा किइका वर्षिक खर्च असन रह गदा है, जबकि सरकार इनें 3000 पोंड दे ही है. इनमें सिमोन नाम के एक सजन थे, जो बीस बर्यों से हेंगेझ (नशा) के वश में थे. इस बल्लाव नैसिमोन का जीवन बदल दिया. सिमोन ने कहा कि फलली बार मेरे जीखन में कुछ नया घट रूल है. मैंने खुद अपनी देख फात शुर्त की है, अपनी सफाई, जारों में टे बचे है सोग के हे सल है, जलि मेर दो बचे है. उस प्रयोग के डढ़ सल
बाद, तेर में से सात सड्य पर सोने वाले लोगों के सिर के ऊपर अपनी छत यनो आना घन हो चुका थ. दो और अपने नवे घरों में जाने वाले थे उस तरह सडक पर रहने वाले 13 लोगों को संधे पसे मिलने की स्थिति ने उनका जीवन ही बदल दिया अनंने पदईई मेंदिलचस्पी ली. खाना बनाने के काम में रुि दिखाड. अपन परखारार से मिलन-ज़लने थेजन मे जे एक गाणिक कर्यकर्ता ने का इम प्रदोगों ने इन लोगों को अधिकास्यंयन बनागा मैका दिया कि अपने जीवन में हसाक्षेप कर सेंके नये प्रयोग कर सकें, अपने को बदल सेंकें कई दाकों से सरा सार या उसकी एजेंसियं इन लोगों को सडक से छटमे का लए दाडत करने, दवाब डालने समझाने, अवलती मकृमा जसे काम करीी रहीं. प हालात वैदे ही हों इन सव पर लगभा सावन


आधार के प्रयोग को रोकना उचित नहीं

50 हजारपौड खर्य होता री. इनसे ज़ड़े सामारिक कार्यकर्ताओं पर खर्चं अला था. इस नये प्रयो बल्ल दिया
इस फ्रयोग को देख कर डुनिया की मशहु पत्रिका 'द इसोनोंमिए्ट', ने लिखा, आवासविकीसड़कों पर रहने वाले लेगों पर खर्च का सबसे
 दरअसत डायेक्ट बनिफिट स्कीन का ऐसा हो
प्रत्यश अपर भारत में दिखेग जब सीधे गरीब
 अपने हक का प्सा अयन हाथ में पाएये तो इससे
गरींों को अपननी नियति और भविष्य बदलने का सपना एक नया रूप लेगा. सरकार की बचत अला होगो. इसके प्रयोग से भारत के पालियायमेंट को दो गयी सुचना के अनुमार पेट्रोलिदम मंत्रालय ने अपने सवें में तीन करोड जाली या फर्जी गेसधारफों की पहचान की चर्चां की है. यानाट्टेड नेशन की एक उल्लेख है कि आयार की बदूलत भरत में उज उल्लेख है कि आयार की बदोलत भार में कुजा
सस्सिर्डमे एक विलियन ऊौनर की बचत संभव है जाने -ाने आर्थिक पत्रकार व अर्थिंक रजनीतिक नीतथयों के अध्येता शकर अथ्यर की
 की भूमिका में चत करते है- करति क्य है? उता मशहु अर्यशास्त्रो जॉन कीनीथ गॉलत्रेथ को उद्ध करते है कि सभी सफल क्रोति हा संड़े-गले दववाजां को घ्वस्त करने की दास्तो हैं, इसी रूप में यनिक
 हबियार देता है कि वे साबित कर सकें कि 'आ
 तथ्थों के अधर पर वह बताते है कि पिछले क दशकों में सरकारों ने करतताओं के अरबं-खरानी रुप्ये सबिडी के रूप में गरीबों के विकास के लि दिय. उकी दुतिया में छाये अंधेरें मेंरनी के लिए वर्चकिये
छात्तववात के रूप में पेशन के रूप में या अन्न सामाजिक कल्याण के कामों में. वह खचं देश का
 चकत्तयों को बा जिनका इस पर वाश्तविक हल था, उन तक पहुंचो ही नहीं. बीच में बिचोलिय खा गये. चह याद दिलत्ते हैं कि शायद नयी पीले को मालूम न हो. वर्षं 1985 की घटना. ओंदेश के कालाबरंडी मे एक निवांमित महिला फननस को वा अरहान थी. उसने अपनी 12 बर्थाय ननद को
 तब ऐरी खं खरें राष्ट़ीय अख बारों की सुर्खियां बनतो बा. पृ दे दे में इसे लेकर आक्रोश उमा. तकालीन प्रधानमंत्री गजोव गांधी उन गर्मियों में वहां गये वही की स्थिति टेखकर सत्ध रह गटे अभिजल परिवार और अभिजाल परिवेश में पले-बढ़े गजजीव
गंथी के लिए वह स्थिति सदना थी. वह नेक इसनान गंथी के लिए यह स्थिति सद्सा थी. वह नेक इसान
थे. पिरिशितिकि गतनीनि में आये पे रज्नेत नहीं हुए थे. दिल्ली लौटकर उन्हिने लगातार का महलपपूर्ग बैठके बललयंद्यौकरहाही को का कि इसका हल निकालें.
शकर अखर को पुरकक में दयये गये आकड के अनुसार 1986 -87 में भारत खाय और उवरके


यह जीडीपी का 1.7 फीसदो था. और सामाजिक बलियन रुयदे खर्च करता थ. पर इन गेजनाओं के लिए अवंटित यह राशि बहुत कम मत्रा में
 पहुंचते 100 पसे में 15 पैसे रह जाती थी, कुछ
दिनों के बाद राजाव गाधी रजस्थान गये, वहा भी दनों के बाद राजीव गौधी रास्थान गये, वहा भी
यनी स्थिति देखी. मारतीय आबादी का 40 फीसदी यही स्थिति देखी. मारतीय आवादी का 40 फीसती
हिस्सा गरोबी झेत रहा था. फिन बंवई के कत्रेस हिस्सा गोबी झेत रा था. फित वंकई के कत्रेस
अधिवेन में उन्नोंने अपनी इस पौड़ा को स्वर अधिवेशन में उन्नान अपपी इस पोड़ा की स्वर
दिया अंड़शा और रजस्थथन के अनुभवों को द्या ओंडशश और रजस्थाम के अनुभवो को
शब्द दिया. कहा, गरोबो उन्मलन के कार्यक्रमों में यदि 100 रुपये उसर से अवंटित होते हैं तो नीचे 15 रुपया ही पहुंच पाते हैं. बीच की यह राशि 85 रुपये) प्रशासनिक खर्चविचौलिये, सता के टलल, ठेकेदार और पष्टों की जेष में जाती है. उड़़सा की फनुस जैसी महिलाएं, सबसे गरीब महिल (शायद गाधा का आतम व्यांक) तक आति-अते सरकारो
'विकास की यह नी' सख जाती है से गरीबं का विकास की दूह नदी साख जाती है. से गररीब का समाज के गरीब लोगों के लिए ससते दर पर चाबल गाह. तेल, किरासन तेल और चौनी भेजती है सार्वंजनिक वितरण प्रणाली के तहत, पर घंटों-घंटों लाइन में खंडे रहले के बाद उनके पर य रसोई तक गहुचते-पहुंचते जन वितरण प्राली का यह सागर सूख जाता है वे वे दास घर की और लौट जाते हैं. 1985 में येजना अयोग का निख्य उनकी रसोई तक पहंचाना था, उनमें से एक की अनियमित अपपत्ती और वराव गुणवत्त के कारग गरिबंों के बीच नबंबं पहुंच रह. शंकर अव्यर की गुसक में गल्लेख है कि 1985-2004 के बीच छह महत्वपूर्ं अध्ययन हुए जिनमें वल्ड वैंक अंर योजन आयेग के अध्ययन भी शामिल है सका नियर्य था कि सारंजनिक आर्पूर्fि के
 माने पर लकेज या भप्टाचारह ह. इस बाच 198 रें धी, बछ़कर 2004 में 270 बिलियन हपये हो थी, वछकर 2004 में 270 कितियन हुपये हो
गयद. 2004 मे योजना आयोग के एक मूल्यांकन में पता चल कि 2003-2004 के बीच 16 राज्यों को गरीबों तक पंछंचाने के लिए 14.07 मीटिक हन खा्यान दिये गये, पर महज 5.93 मीट्रिक टन खाधन्न ही बीफएल परिवारीं तक पहुच पाये.
2005 में योजन आयोग के एक अध्यान ने बताया 2005 मे थोजना आयोग के अक अध्यदन न बतावा खर्यान बीी़ेए परीविरों तक इसलिए नीीं पहंचे क्योंकि उनकी पहचान में पूल हुं, गा उनका अतापता ही नहीं था. वितरण में अपारदशंता थी. खुली लूट और प्रष्टाचर उपर से 2008 में योजना अयेग के आप्यक्ष मेंटिक सिंह अहलूवालिया ने पुन: 23 वषों बाद गजीव गाधी की बात तोहराही कि पैंसे ही उन तक पहांच रहे हैं, यानी ब्यस्थ के शीर्ष पर बेठे लेगों को सब प पता था, पर या तो ने असहाय थे याबोच की लट मे लगी तक्तों के आगे समर्पत अर उनकी सेवा में ेे
शंकर अबर की पुस्तक में दर्जं तथ्यों के अनुमार सिर्फ जनवितरणा प्रणली के खाद्यनों में ही दह लटट नही हो री थी, ऊर्जा के नाम पर जो सक्किजि, किकासन तेल, एलपीजी गैस और डीजल के लिए दिया जा रा था, बह 2002 में
62 बिलियन रुपने था. 2009 में बढकर 760 62 बिलयन रुपवे था. 2009 मे बहुकर
हपये विलियन को गया. घेंल गिस याने एलपीजी का लाभ उाकोो भी मिल कल धा. जो प्रनिया के शीर्ं अर्मरों में से एक हैं, लगभा दो दएकों बाद वर्ष 2008 में गुहुल गाधी ने भी अगने पिता राजीव गांधी की वातों को ही देहाया. 23 वर्षों बाद. किसी संवेदर्रील व्यवस्था में यह प्रश स्वाभाकिक स्प से उठता कि पिता प्रभनममंत्री राजाव गधान न भी यदी
का इसके बाट कापस के नगमंह गव मनमोहन संह या विस्ट की मिलीजली सकाों की सत्रधर वरी. वह क्यों नहीं इसे र्रांने के लिए कुछ कर पायी? क्या वह असलाय या अक्षम थी या सता में रहते व्ववस्था की गभरार लट को सवाल उठा कर फह नायक-खलनयक दोनों की भूमिका में रहना चाहती थी. साथ ही लुट की वह व्यवस्था किसके

> आधार को लेकर कुछ और गंभीर लोगों ने अनेक प्रासंगिक सवाल उठाये हैं. येलोग तकनीकी पक्ष के भी गहरे जानकार हैं इनमें से एक कर्नल मैथ्य थॉमस से हमारी मुलाकात कुछ महीनों पहले हुई. उन्होंने ऐसे अनेक तथ्य आधार को लेकर बताये जो गंभीर सवाल खड़े एरते हैं. सरकार और आधार को तकनीकी रूप से श्रेष्ट और सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य माननेवाले लोगों को इन सवालों के जरूर उत्तर देने चाहिए पर आधार के प्रयोग को रोकने की बात कहीं से उचित नहीं है.


ल्य को किन्रों करणों से अघंषित संश्रण हे रही थी. क्योक 70 वरों की आजादे में सबसे अधिक थी, क्यींक 70 वष्,
राज उसका रू है.
उदरीकरण के बाद 1991 से 2010 के बीच भारत का खर्च ब्वाद्यान ऊर्जा और उर्वरक की सलिडी पर 122 विलियन रुपे से बढ़कर 1.73 द्रिलियन रयवे हो गया. और इसी बीच सानाजिक क्षेत्रों में केंद्र और रज्यों का कुल खर्चमिलकर 102 बिलिगन म्यके से $5, \supset 9$ ट्रोलगयन कपये हो गया एक तरक सब्सिडी और गरीबबं के कल्यापे के सरकारी खच पर वेतहाशा वाद्ध हुं पर उसका तो जिनने घर थे, की उससे अधिक गशन कार्ड थे इस तरह भारत का भविथ्य आर विकास, भ्रष्टाचा के अंयेंरे ने निल लिया था. 'आधार' ने उम्मी पैदा की है कि सही आदमी को प्रहामकर उसक् मदद की जावे. सीधे उसके हाष में उसका हिस्स देकर, पहांचाकर. ताकि वह अपन्नी नियति का खद्व मालिक बन सके, किसी बचौलयय य भाप्ट अफसर
के रूमोकरम य द्या पर मवस्सर न रहे. 23 अगस्त को भारत सरकार ने सचना ही है मि मली़ेशन कंपनियों समेत निजी क्यनियों ने तीन चर्ष में तीन मीनों में 1.52 लाब करोड रुपये की टैस्त चरी का है. सरकार ने इस मामल मे जाच सरे का निधंरण, टैक्स की वसूलो, जुर्माना और क्रिमिनल कोर्ट के सामने मामला दासर करने का काम मी शुरु कर दिया है. टाइ्स ऑफ़ इंडिया की सूचना सयदे की आठ की सचना नबींदेने की बान स्वीका कर ली है. अब अप फ़ंज करे! सेंट्रत ए एक्वाइड सविसं टैक्स और कस्टम में किस तरह इस तरह की चोरिया होती रहीहैं, आरइन सब कर टेने वलों की प्रणान इके खाता से जड़े तो टक्स चोती असान नली रह जायेगा.

ने जो कानून बनाये या काम किये है. उनका असर साफ दिख रहा है. अयक्र देनेवालं की संख्या
25 पीसदो की बढ़ोतरी पांच आग्त तक हुई है नोटबंदी का अलग असर कश्मीर के पत्थखाजों और नक्सली गतिविधि परहुआ है 24 जलाई को सुतीम कोटे के दो जजं एके सोकरी और अरोक भ्ष गे ने माना कि कल्याणका
 (लेजिटीमेट स्टेट इंटोस्ट) है, 155 पे पे के फिसल में कल कि दह कान्न बनाकर राजसता अपनी सोमा से बाहर नढी जा रही है. विभिन्न योज्माओ से अधार को जोड़ने में कों पूर्वाय़ह भी नहीं उचतम न्यातातय ने अभने इस आंदेश में काणि संसद को प्रासंीक कानून काने का इक है. जल ने कहा कर राज्य का फल है कि वह वसी थाजनाए नो वचित वर्गों के हित में हो राजसत्ता यह भी सुनि. कल्यापकारी कमों में पष्टाचार या लीकेज प उस प्पठ ने टिपणी की 'इस बात पर स्शय नहींकि
 को नियंत्रित किया ज सकता है. कोर्ट ने यह भा कहा कि आधार से फज्जों या देहा लाभ लेनेवाले लोगों की मी पहचान हो सेकेगी, जे वाजिब लोंग का हक मारो है, लभ लता है. अदालत ने यह लगी संश्या अतंक्वा अपाभ मीलाड़ी पष्टाचार और ब्लैक मनी नियंत्रित करने में मश्ष लोंगी. उच्चतम न्यायातय ने यह़ भी का कि फे की आधार और बायोमोट्रिक पद्वति से जोइक बेहतर बनने को जरूत है. क्योंकि जो लोग अनेक पैनकाई रखते हैं, उनका मकसद स्पट है कि
 उतन सम ने अपनेनी विवेक के तहतन कह विएर कि कि एक आदमी के पास एक फैका है होने ये औ? वह आधार से जुड़े होने से चीजें नियंत्रति होगी सरका ने आठ आस्त तक 11.4 लाख पेनका को निस्त्त कर दिया है, क्योंकि अबतक झन लोगों के पास एक से अधिक पैनकारं था. सष्ट बनुत हद तक भ्रच्टचार, काल घन या गरकानू तितिधियां नियोत्रत की जा सकती है
पर. आधर येजन के इस प्रयोग का विरोष
 जीवन मे इसतथष्षे कर सक्ती है. निगरानी राव सकती है. आइडेंटिटि कंट्रेल कर सकती है. इस तरह लोगं की प्राइसेी खतर में होगी. आधार की लेकर कुछ और गंभेर लोगों ने अनेक प्रासंगिक सवाल उठाये है. ये लेग तकर्नीकी पक्ष के भी गह जानकार हैं, इनने से एक कनल मैथ्यू थामस
 गभभर सवाल खडे करते है. सरकर और आधा को तफन्नीफी रूप से श्रेष और सरक्षा की दृप्टि अंपय माननेवले लंगों को इस सबालों के जह उतर देने चाहिए पर, आधार के प्रोंग को गेक की बात करंं से उचित नहीं हैं
दरअसत एमारे मुल के बौन्दिक के साथ गथार समश्या है. वे उदरता को खच्छंदता मानल
है प वरां उवर समाज और ह. पर वां उदार समाज ओर उदार मूल्यों को
बचाये रखने के लिए जो व्यवस्थात्रापथन है बचाये रखने के लिए जो व्यवस्थागत प्रवधान है
उनं माने के लिए तैवार नीै है यह खच्छंसा है स्वछंता या ख्वअनशयन का न होना या नियम कानून कोन मान्ना उदरता पर प्रहार है. आधार वे भामले में कम से कम ऐसा ली हो रा है . स्वीडेन की किन्नी दुनिया के श्रेछ देशों में होती है, जां सबसी नहतर सामांजक सुग्शा के प्रतधान हैं समाजबादी विचारधारा के लोगों के लिए तो आदर्श मल्क है,
वहां सबका आइडेंट्वि कड़ं है गरब पर पीरिंध
 ग्याइह से सात तक दुकाने खली रहती हैं. लोग आइडेंटिटी कार्ड लेकर शराब ले सकते हैं. लगमग हर जगह आइंडेंटिट काई की जसरत्र है. हल में एक पित्र बहं एक विथवधिलब में पदाने गये. जब तक उनका आहडी काड नर्धा बना, बेक अकाडट नहीं खला. इसी तरहा सिंगपर रें विना आइडी काड आप नहंँ घुन सकते. कभी भी आएई काई मांगा
जा सकत है यदि आप कटते हैं कि घर पर कर गया है तो पलिस घर तक सथ वह देखेने जायेगी इसी तरहह अमेरिका में सामाजिक सरखन नंबर या पहचान अनिवार्यहै इस तार यूोप के सणी देशों में यही स्थिति है. चौन रूस और अन्न देशं की बात तो छोड़ही दे ! वांां तो पहचन के कठिन प्रावधान है. अंस्ट्रिलिय में भी पहचन के सबा प्रवधान कम उग्र के बचे शराब नौीं खरीद सकते.
इस संदर्भ में महायम गांधी से बेत्वर और
प्रमाणिक कौन हो सकता है उनके अनेक कथन है, जे सट्ट करो हैं किस्वच्छंदो की बनियद पर उदरता का पाहोलन नहीं बन सकता. स्वअभनास्से या मानाजिक अनिशसन के बिना आराजकता स्वत आयेगी. इसलिए अराजक्ता को तोकने के लिए ध्राचार को रेकने के लिए ऐसे कान्नी प्राबधनों
का हैना भार के हित में है. से

